



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2017/ज्येष्ठ 11, 1939
No. 145] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/JYAISTHA 11, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2017

मामला सं. OI/03/2017

विषय : चीनी ताइपेई और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से डाओक्टाइल फ्थेलेट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/2/2017-डीजीएडी.—मै. केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता/आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीनी ताइपेई और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से डाओक्टाइल फ्थेलेट (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या डीओपी भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

- और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को उचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह याचिका मै. केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लि. जो भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक हैं, ने दायर की है। भारत में उत्पाद के अनेक अन्य उत्पादक हैं। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि पीसीएल आयल और पायल पालीमर्स उत्पाद का आयात कर रहे हैं। आवेदक संबद्ध वस्तु के दो आयातकों से संबंधित है। संबंधित कंपनियों द्वारा किया गया आयात कुल आयात का 2.3 प्रतिशत, उसका उत्पादक का 2.1 प्रतिशत और मांग का 1.1 प्रतिशत है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं।

4. यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है और इसलिए उनका घरेलू उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। याचिकाकर्ता नियमावली के अर्थ के भीतर वर्तमान याचिका दायर करने की योग्यता को पूरा करता है और घरेलू उद्योग है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "डाओक्टाइल फ्थैलैट(डीओपी)" है। इसे रासायनिक रूप से बिस (2-इथाइलहैक्सिल) फ्थैलैट के रूप में जाना जाता है और संक्षिप्त रूप में डीईएचपी भी कहा जाता है। डाओक्टाइल फ्थैलैट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र $C_8H_4(C_8H_{17}COO)_2$ है।

6. डीओपी सबसे महत्वपूर्ण "फ्थैलैट" है जो थलिक एसिड और ब्रांच्ड श्रृंखला 2-इथाइलहैक्सालनोल का डायेस्टर है। यह रंगहीन तरल तेल में घुलनशील है परंतु जल में नहीं। इसमें अच्छी प्लास्टिसाइजिंग विशेषताएं हैं। चूंकि अनेक कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जाता है इसलिए इसके अनेक नाम और संक्षिप्त नाम बन गए हैं जिनमें डि-सेक आक्टाइल फ्थैलैट, डीईएचपी, डि (2-इथाइलहैक्सिल) फ्थैलैट, आक्टाइल फ्थैलैट शामिल हैं।

7. संबद्ध वस्तु का व्यापक रूप से प्रयोग पीवीसी की वस्तुएं बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर के रूप में होता है। प्लास्टिक्स में जरूरत के अनुसार डीओपी की 1 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की मात्रा हो सकती है। इसका प्रयोग हाइड्रोलिक तरल के रूप में और कैपेसिटर्स में डायलैक्टिक तरल के रूप में भी होता है। इसे ग्लो स्टिक्स में विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उपयुक्त विशेषताएं और कम लागत होती है। इस उत्पाद को प्राथमिक रूप से भार के आधार पर बेचा जाता है।

8. विचाराधीन को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन अध्याय 29 में 29173920 पर वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद और वर्तमान जॉच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदक ने बताया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अंतः वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

घ. शामिल देश

10. वर्तमान जांच चीनी ताइपेई और कोरिया गणराज्य (कोरिया आरपी) (जिन्हें संबद्ध देश कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

इ सामान्य मूल्य

11. याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना के अभाव में और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य को परिकलित किया गया है। प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री, सुविधाओं और परिवर्तनलागत से संबंधित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए उन्हें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों जमा तर्कसंगत लाभ के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके परिकलित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावों की जांच की है और पाया है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

च. निर्यात कीमत

12. आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का दावा डीजीसीआईएस द्वारा प्रकाशित आकड़ों के आधार पर किया गया है। कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़े और पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के संबंध में कीमत समायोजन किए गए हैं। निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

छ. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पाटन मार्जिन के निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

14. आवेदक ने सूचना प्रस्तुत की है और पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बढ़ी हुई मात्रा, भारी कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, लाभप्रदता, निवेश पर आय, नकद प्रवाह, मालसूची आदि जैसे मापदंडों के आधार पर संचयी और समग्र रूप से घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में खराबी के परिणामस्वरूप कथित पाटन के फलस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं।

ज. जांच अवधि

15. आवेदक ने जाँच अवधि के रूप में अप्रैल 2015 से सितंबर 2016 (18 महीने) की अवधि का प्रस्ताव किया है। तथापि अधिक अद्यतन आकड़ों पर अपेक्षित विश्लेषण करने में प्राधिकारी को सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकारी ने अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 (12 महीने) तक पीओआई निर्धारित की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जाँच अवधि शामिल होगी।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:—

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग,

नई दिल्ली- 110001

ञ. समय-सीमा

17. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

18. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरुआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

ट. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

19. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

20. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

21. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

22. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

23. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

24. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

25. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ड. असहयोग

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2017

Case No. OI/03/2017

Subject: Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Diocetyl Phthalate (DOP)” originating in or exported from Chinese Taipei and Korea RP.

F. No. 6/2/2017-DGAD.—M/s KLJ Plasticizers Ltd. (hereinafter referred to as “petitioner/applicant”) has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Diocetyl Phthalate (hereinafter referred to as the ‘subject goods or DOP’) from Chinese Taipei and Korea RP (hereinafter referred to as the ‘subject countries’).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the quantum of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

A. Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed by M/s KLJ Plasticizers Ltd. who is a major producer of subject goods in India. There are a number of other producers of the product in India. Petitioner has contended that PCL Oil & Payal Polymers are importing the product. The applicant is related to two importers of the subject goods. Imports made by related companies is 2.3% of total imports, 2.1% of its production and 1.1% of demand. These imports were used as input for production of other products. Authority has considered the petitioner as an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.

4. It is seen that production of the petitioner accounts for significantly beyond 50% of the Indian production and thus constitutes “a major proportion” of the domestic production. The petitioner satisfies the standing to file the present petition and constitutes “Domestic Industry” within the meaning of the Rules.

B. Product under consideration

5. The product under consideration in the present petition is “Diethyl Phthalate (DOP)”. It is chemically known as Bis (2-ethylhexyl) phthalate, also abbreviated as DEHP. Diethyl phthalate is an organic compound with the chemical formula C₈H₄ (C₈H₁₇COO)₂.

6. DOP is the most important “phthalate,” being the diester of phthalic acid and the branched-chain 2-ethylhexanol. This colourless viscous liquid is soluble in oil, but not in water. It possesses good plasticizing properties. Being produced on a massive scale by many companies, it has acquired many names and acronyms, including Di-sec octyl phthalate, DEHP, Di (2-ethylhexyl) phthalate, Octyl phthalate.

7. The subject goods is widely used as a plasticizer in manufacturing of articles made of PVC. Plastics may contain 1% to 40% of DOP depending upon requirements. It is also used as a hydraulic fluid and as a dielectric fluid in capacitors. It also finds use as a solvent in glow sticks as it has suitable properties and the low cost. The product is primarily sold on weight basis.

8. The product under consideration is classified under Chapter 29 under the Customs Tariff Act, 1975 at 29173920. The customs classification is indicative and not binding on the scope of the product under consideration and present investigations.

C. Like Article

9. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as “like article” under the Rules. For the purpose of the present investigation, the Authority considers the subject goods produced by the applicant in India as “Like Article” to the subject goods being imported from the subject countries.

D. Subject Countries

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Chinese Taipei and Republic of Korea (Korea RP) (referred to as the “subject countries”).

E. Normal value

11. The petitioner has submitted that in absence of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject countries, and in absence of any documentary evidence, the Normal Value in the subject countries have been constructed. The Authority has considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values taking into account best information available concerning cost of raw material, utilities and conversion costs, duly adjusted on account of selling, general & administration expenses, plus reasonable profit.

The Authority has examined the claim of the petitioner and finds that there is sufficient prima facie evidence of normal value of the subject goods in the subject countries.

F. Export Price

12. The applicant has claimed the export price for the subject goods on the basis of DGCI&S published data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, port and inland freight expenses and bank charges to arrive at net export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence with regard to the export price.

G. Dumping Margin

13. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is insufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries. The dumping margins are estimated to be above de minimis limits for each of the subject countries.

Injury and Causal Link

14. The applicant has furnished information and has claimed injury to the domestic industry as a result of dumped imports in the form of significant increase in imports in absolute terms as also relative to the production and consumption in India, significant price undercutting, price suppression, deterioration in performance of the domestic industry collectively and cumulatively on the basis of parameters such as capacity utilization, market share, profitability, return on investments, cash flow, inventories, etc.

H. Period of Investigation

15. The Period of Investigation (POI) proposed by the applicant is from April 2015 to September 2016 (18 months). However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority has fixed the POI as April 2016 to March 2017 (12 Months). The injury investigation period will however cover the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and period of investigation.

I. Submission of information

16. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street
New Delhi - 110001**

J. Time limit

17. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

18. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

K. Submission of Information on Non-Confidential basis

19. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

20. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

21. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

22. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the

substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

23. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

24. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information

L. Inspection of Public File

25. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

M. Non-cooperation

26. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority